आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण

भारत संघ एवं अन्य

3 मई, 2006

(बी. पी. सिंह और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.)

1. भारत का संविधान-अनुच्छेद 289 -आयकर अधिनियम, 1961 -धारा 10 (20)और 10(20 ए)-बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974-धारा 7 एवं 17-राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकार की आय प्राधिकरण के बैंकर को राजस्व द्वारा जारी नोटिस प्राधिकरण की सावधि जमा पर अजिर्त ब्याज आय के स्रोत पर आयकर कटौती करने के लिए -नोटिस को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई-सही ठहराया गया, प्राधिकरण एक अलग कानूनी इकाई है-प्राधिकरण की आय राज्य की आय नहीं है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद, 289 के तहत छूट का हकदार नही है-प्राधिकरण कोई स्थानीय अधिकारी नहीं है जो आयकर अधिनियम की धारा 10 (20)के तहत छूट का हकदार है-वित्त अधिनियम, 2002 -सामान्य खंड अधिनियम, धारा 3 (3)

2. राजस्व ने अपील कर्त्ता के बैंकर को एक नोटिस जारी किया-1 अप्रैल, 2003 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (20ए) की चूक

और धारा 10 (20)में स्पष्टीकरण जोडने के मद्येनजर प्राधिकरण की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज से स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा। अपीलकर्ता ने राजस्व के नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए रिट याचिका खारिज कर दी कि नोटिस कानूनी और वैध था।

3. इस अदालत में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 3 (3)और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 की धारा 7 को ध्यान में रखते हुए एक स्थानीय प्राधिकरण है और इसलिए इसकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के तहत करमुक्त है; यह राज्य की एक एजेंसी है जो व्यापार या व्यवसाय नहीं करती और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 289(1) के अन्तर्गत आती हैं, जो राज्य की संपत्तियों और आय को संघ काराधान में छूट देती है, और यह कि आयकर अधिनियम में संशोधन संविधान के अनुच्छेद, 289 के संदर्भ में किया गया था।

4. राजस्व ने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 (1) के तहत, केवल राज्य की आय, न कि राज्य के अधीन किसी प्राधिकरण की आय को संघ कराधान से छूट हैः, अपीलकर्ता की एक अलग कानूनी इकाई है और इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी आय राज्य की आय हैः, और यह कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास

प्राधिकरण अधिनियम, 1974 की धारा 17 के तहत, राज्य किसी भी प्राधिकरण को भंग कर सकता है और इसलिए, एक आवश्यक परिणाम में जब तक प्राधिकरण भंग नहीं हो जाता, तब तक इसकी संपतियां, धन और बकाया प्राधिकरण के हैं, न कि राज्य की।

अपीलो को खारिज करते हुए, न्यायालयः-

अभीनिर्धारितः 1.1 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 की धारा 17 के अनुसार, उक्त अधिनियम के तहत गठित अपीलकर्ता प्राधिकरण की आय उसकी अपनी आय है और प्राधिकरण अपने धन का प्रबंधन स्वयं करता है। इसकी अपनी संपतियां और देनदारियां हैं। यह अपने नाम पर मुकदमा कर सकता है या मुकदमा दायर कर सकता है। भले ही, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के खंड (2) के तहत व्यापार या व्यवसाय नहीं करता है, फिर भी यह राज्य की विधायिका के एक अधिनियम के तहत गठित एक प्राधिकरण है, जिसका एक विशिष्ट कानूनी व्यक्तित्व है, जो एक कॉपरेट निकाय है, जो राज्य से अलग है। अधिनियम की धारा 17 आगे स्पष्ट करती है कि इसके विघटन पर ही इसकी संपत्ति, धन और देनदारियां राज्य सरकार को हस्तांतरित होती है। इसलिए आवश्यक रूप से इसके विघटन से पहले, इसकी संपत्तियां, निधियां और देनदारियां इसकी अपनी हैं। इसलिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि प्राधिकरण की आय राज्य सरकार की आय है, भले ही प्राधिकरण का गठन

राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम के तहत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके किया गया हो (764 जी-एच, 765-ए -बी)

1.2 करदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(20 ए) द्वारा प्रदत्त लाभ स्पष्ट 289(1) रूप से छीन लिया गया है। इसके अलावा, धारा 10(20) में जोडा गया स्पष्टीकरण "स्थानीय अधिकारियों" की गणना करता है जो यहां निधार्रित को कवर नहीं करते हैं। अपीलकर्ता\प्राधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 289(1) के तहत संघ काराधान से छूट का दावा नहीं कर सकता। इसलिए, आयकर अधिकारियों द्वारा जारी किया गया नोटिस वैध और कानूनी था।

आंध्र प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम बनाम आयकर अधिकारी और अन्य, (1964) 7 एससआर 17, पर भरोसा किया गया।

भारतीय खाद्य निगम बनाम नगरपालिका समिति, जलालाबाद और अन्य (1999)6 एससीसी 74, विशाखापत्नम पोर्ट ट्रस्ट बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के लिए न्यासी बोर्ड, (1999)6 एससीसी 78, भारतीय खाद्य निगम बनाम नगरपालिका एच समिति, जलालाबाद और अन्य ए आइ आर (1999) एससी 2573 दम दम नगरपालिका के नगर आयुक्त और अन्य बनाम भारतीय पर्यटन विकास निगम और अन्य, (1995)5 एससीसी 251;केंन्द्रीय भंडारण निगम बनाम नगर निगम (1994)सप 3 एस सी सी 316 और वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड बनाम विशेष क्षेत्र विकास

प्राधिकरण, कोरबा और अन्य और भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बनाम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, करबा, और अन्य, ए आई आर (1982) एससी 697, संदर्भित।

श्री रामरतनु सहकारी हाउंसिग सोसायटी लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (1970) 3 एससीसी 323 और नई दिल्ली नगर पालिका समिति बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1997) 7 एससीसी 339 प्रतिष्ठित।

भारत के संविधान पर बसु की टिप्पणी 6वे संस्करण खंड एल का उल्लेख किया गया है।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या, 6382/2003

2003 के डब्ल्यू पी (टी)संख्या 1222 में झारखंड उच्च न्यायालय रांची के निर्णय\आदेश के दिनांक 08-05-2003 से।

अपीलकर्ता की ओर से के के वेणुगोपाल, विकास सिंह, मनीष मोहन, अमृता नारायण, यूनुस मलिक और प्रशांत चौधरी,

प्रतिवादी की ओर से टी. एस. दोआबिया, मनीष शर्मा और बी. वी. बलराम दास

न्यायालय का निर्णय वी पी सिंह ने सुनाया गया:-

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसमें अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका द्वारा आयकर उपायुक्त, टीडीएस सर्कल जमशेदपुर द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जमदेशपुर के प्रबंधक को 14 फरवरी, 2003 को जारी नोटिस को चुनौती दी थी। जिसमें प्रबंधक के ध्यान में लाया कि वित्त अधिनियम, 2002 ने आयकर अधिनियम में बदलाव लाए हैं और जबकि धारा 10(20ए) को हटा दिया गया था, अधिनियम की धारा 10(20) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। संशोधन के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के जो प्रावधान बने हुए थे, वे बैंक को अपीलकर्ता /प्राधिकरण की सावधि जमा रसीदों पर अर्जित ब्याज से स्रोत पर आयकर काटने के लिए बाध्य करते थे। बैंक के प्रबंधक को प्रावधानों का अनुपालन करना और स्रोत पर कर की कटौती करना और अनुपालन की रिपोर्ट करना आवश्यक था। उपरोक्त रिट याचिका पर रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने 8 मई, 2003 को अपना फैसला सुनाते हुए रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आयकर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर, नोटिस वैध और कानूनी था। अपीलकर्ता/प्राधिकरण ने विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश पर आपत्ति जताई है।

2. अपीलकर्ता/प्राधिकरण का गठन बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 के तहत औद्योगिक क्षेत्र के नियोजित विकास, उद्योगों को बढ़ावा देने और उससे जुड़े मामलों के लिए किया गया है।

अपीलकर्ता/प्राधिकरण एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर है, जिसके पास चल और अचल दोनों संपत्तियों को प्राप्त करने,रखने और निपटान करने, अनुबंध करने और उक्त नाम से मुकदमा करने या मुकदमा करने की शक्ति है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पांच अन्य निदेशक शामिल हैं। प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार है जिसमें क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करना और क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना और उससे जुड़ी अन्य सुविधाएं शामिल हैं। प्राधिकरण की अपनी स्थापना है जिसके लिए वह राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से नियम बनाने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकरण को नियोजित विकास, या औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव और उसकी सुविधाओं और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई भी कार्य सौंपने के लिए अधिकृत है। अधिनियम की धारा 7 प्राधिकरण को अपना स्वयं का कोष बनाए रखने के लिए बाध्य करती है जिसमें प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्यथा अधिनियम के तहत प्राप्त सभी शुल्क, किराए, शुल्क, लेवी और जुर्माने के रूप में प्राप्त धनराशि जमा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा अपनी चल या अचल संपत्तियों के निपटान से प्राप्त सभी धन और वित्तीय और अन्य संस्थानों से ऋण के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन और राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित प्राधिकरण की एक योजना या योजनाओं के निष्पादन के लिए जारी डिबेंचर

जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन को उसके कोष में जमा किया जाएगा, जिसे भारतीय स्टेट बैंक और/या एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास रखा जाएगा और प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर निकाला जाएगा।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 289 इस प्रकार प्रदान करता है:-

"289. किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट-(1) किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट दी जाएगी।

(2) खंड (1) में कुछ भी संघ को किसी भी सीमा तक, यदि कोई हो, किसी भी कर को लगाने या लगाने का अधिकार देने से नहीं रोकेगा, जैसा कि संसद कानून द्वारा किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय के संबंध में प्रदान कर सकती है, या किसी राज्य की सरकार की ओर से, या उससे जुड़े किसी भी संचालन, या ऐसे व्यापार या व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली या कब्जा की

गई कोई संपत्ति, या उसके संबंध में अर्जित या उत्पन्न होने वाली कोई आय।

(3) खंड (2) में कुछ भी किसी भी व्यापार या व्यवसाय, या व्यवसाय के व्यापार के किसी भी वर्ग पर लागू नहीं होगा जिसे संसद कानून द्वारा सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक घोषित कर सकती है।"

4. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। आयकर अधिनियम का अध्याय III उन आय से संबंधित है जो कुल आय का हिस्सा नहीं हैं। धारा 10 का प्रासंगिक भाग जैसा कि यह 62002 के वित्त अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले था, इस प्रकार पढ़ा गया:-

10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना मे निम्नलिखित में से किसी भी खंड के अंतर्गत आने वाली किसी भी आय को शामिल नहीं किया जाएगा:-

(20) एक स्थानीय प्राधिकारी की आय जो "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" या उसके द्वारा किए गए किसी व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त होती है जो आपूर्ति से अर्जित या उत्पन्न होती है। किसी वस्तु या सेवा (पानी या बिजली नहीं) का अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर या बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से;

(20ए) आवास व्यवस्था की आवश्यकता से निपटने और संतुष्ट करने के उद्देश्य से या शहरों, कस्बों और गांवों या दोनों के लिए योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से अधिनियमित किसी भी कानून के तहत या उसके तहत भारत में गठित प्राधिकरण की कोई आय।

5. 1 अप्रैल 2003 से वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा धारा 10(20) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया और धारा 10(20ए)को हटा दिया गया। धारा 10(20) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-

"स्पष्टीकरण. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है:-

(i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (डी) में उल्लिखित पंचायत; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट नगर पालिका; या

(iii) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के कानूनी रूप से हकदार या सरकार द्वारा सौंपे गए; या

(iv) छावनी बोर्ड, जैसा कि छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2)की धारा 3 में परिभाषित है।"

6. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि गृह संपत्ति से आय",पूजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से आय" या उसके द्वारा किए गए किसी व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त स्थानीय प्राधिकारी की आय को पहले पिछले वर्ष की प्राधिकरण की कुल आय की गणना करना शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, संशोधन के मद्देनजर, 1 अप्रैल, 2003 से, स्पष्टीकरण स्थानीय प्राधिकारी" को केवल स्पष्टीकरण में उल्लिखित प्राधिकारियों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता जैसे प्राधिकारी शामिल नहीं हैं। साथ ही धारा 10(20ए) जो भारत में आवास व्यवस्था की आवश्यकता से निपटने और संतुष्ट करने के उद्देश्य से या शहरों कस्बों और गांवो की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से अधिनियमित किसी भी कानून के तहत गठित प्राधिकरण की आय से संबंधित है, जो संशोधन से पहले कुल आय की गणना में शामिल नहीं थे, हटा दिए गए। परिणामस्वरूप ऐसे प्राधिकारी को (20ए) द्वारा प्रदत्त लाभ छीन लिया गया।

7. उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश में कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 10(20ए) को हटा दिया

गया था और धारा 10(20) द्वारा विचारित "स्थानीय अधिकारियों" की गणना करते हुए धारा 10(20) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था, अपीलकर्ता/प्राधिकरण 1 अप्रैल, 2003 के बाद उन प्रावधानों के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सका। इसमें आगे कहा गया कि अनुच्छेद 289(1)के तहत छूट भी अपीलकर्ता/प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं थी क्योंकि यह एक अलग कानूनी इकाई थी, और इसकी आय को राज्य की आय नहीं कहा जा सकता है ताकि उसे संघ कराधान से छूट मिल सके। इस अपील में उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर आपत्ति जताई गई है।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के के वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3(3) और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियमए 1974 की धारा 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह होना चाहिए कि अपीलकर्ता एक स्थानीय प्राधिकारी है। उनके अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 10(20) के तहत अपीलकर्ता/प्राधिकरण को एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 289 (1) किसी राज्य की संपत्तियों और आय को केंद्रीय कराधान से छूट देता है। अनुच्छेद 289 के खंड (2) का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जा रहे व्यापार या व्यवसाय पर विचार करता है। यह अनुबंध अधिनियम के तहत एजेंसी की अवधारणा

लाता है। इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से, राज्य की एक एजेंसी, जो व्यापार या व्यवसाय नहीं करती है, अनुच्छेद 289 के खंड (2) के अंतर्गत नहीं आती है और इसलिए छूट राज्य सरकार की ऐसी एजेंसी तक बढ़नी चाहिए। उन्होंने इस कोर्ट के कुछ फैसलों पर भी भरोसा किया, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आयकर अधिनियम की धारा 10 में ऊपर उल्लिखित संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के संदर्भ में नहीं किया गया है और यह शायद विधानमंडल के दिमाग में मौजूद नहीं था। उन्होंने ऐसे मामलों में सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण की सराहना की।

9. भारत संघ की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री टीएस दोआबिया ने अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह की गई दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब तक राज्य की किसी एजेंसी या साधन द्वारा उत्पन्न आय सीधे तौर पर राज्य के खजाने में नहीं जाती और राज्य की आय बनी रहने पर, एजेंसी, चाहे निगम, कंपनी या प्राधिकरण हो, अनुच्छेद 289(1) के तहत संघ कराधान से छूट का दावा नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 289(1) के संदर्भ में लागू होने वाली सच्ची परीक्षा यह थी कि क्या अर्जित आय राज्य की आय है। अनुच्छेद 289(1) के तहत संघ कराधान से जो छूट दी गई है वह राज्य की आय है, न कि राज्य के अधीन किसी प्राधिकरण की आय। इस मामले के तथ्यों में उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता/प्राधिकरण एक अलग कानूनी इकाई होने के नाते,

आय अर्जित करता है और अपने स्वयं के धन का प्रबंधन करता है, यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी आय राज्य की आय है। विशेष रूप से, उन्होंने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 की धारा 17 पर जोर दिया जो इस प्रकार है:-

> "जब राज्य सरकार संतुष्ट हो जाती है कि इस अधिनियम के तहत जिस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, वह काफी हद तक हासिल कर लिया गया है, जिससे प्राधिकरण की निरंतरता अनावश्यक हो गई है, तो सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि प्राधिकरण इस तारीख से भंग कर दिया जाएगा। जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है और प्राधिकरण को उक्त तारीख के अनुसार भंग माना जाएगा और प्राधिकरण द्वारा वसूली जाने वाली सभी संपत्तियां, निधियां और देयताओं को उसकी देनदारियों के साथ हटा दिए जाएगी व राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगी।''

उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकार के पास अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से अपीलकर्ता/प्राधिकरण को भंग करने की शक्ति है। उस तिथि से प्राधिकरण द्वारा वसूली जाने वाली संपत्तियां, निधियां और देय राशियां अपनी देनदारियों के साथ राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाती हैं। इसलिए, यह एक आवश्यक परिणाम है कि जब तक प्राधिकरण भंग नहीं हो जाता, तब तक इसकी संपत्तियां, निधियां और बकाया प्राधिकरण के ही हैं, न कि राज्य के। यदि ऐसा नहीं होता तो धारा 17 में यह निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि प्राधिकरण के विघटन की तारीख सेए प्राधिकरण द्वारा वसूली जाने वाली संपत्तियांए निधियां और देय राशियां अपनी देनदारियों के साथ राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगी।

10. अनुच्छेद 289(1) के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि इसके तहत छूट का दावा इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि छूट का दावा किसी राज्य की संपत्ति और आय के संबंध में किया गया है। एक बार जब यह माना जाता है कि संपत्ति और आय राज्य की है, तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या यह अनुच्छेद 289 के खंड (2) के प्रावधान के मद्देनजर अभी भी कर योग्य है, जो प्रमुख रूप से परन्तुक की प्रकृति में है। खंड (2) संघ को किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय या उससे जुड़े किसी भी संचालन के संबंध में उस सीमा तक कोई भी कर लगाने का अधिकार देता है जो संसद

कानून द्वारा प्रदान कर सकती है। इस प्रकार, अनुच्छेद 289 के खंड (1) के अर्थ के तहत राज्य की आय पर भी संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा कर लगाया जा सकता हैए यदि ऐसी आय किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त होती है जिसका संचालन किसी राज्य की सरकार या उससे जूड़े कोई संचालन द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 289 का खंड (1), इसलिए संसद को राज्य की आय पर कर लगाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है जो राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय के माध्यम से अर्जित की जाती है।

11. यह सच है, जैसा कि श्री वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया है, कि अनुच्छेद 289 का खंड (2) संसद को राज्य द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय पर कर लगाने का कानून बनाने का अधिकार देता है। यह संसद को किसी राज्य की आय पर कर लगाने के लिए अधिकृत नहीं करता है यदि ऐसी आय अनुच्छेद 289 के खंड (2) द्वारा अपेक्षित तरीके से अर्जित नहीं की जाती है। हमारे विचार से यह उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है जो इस अपील में हमारें विचार के लिए हम उठता है। अनुच्छेद 289 का खंड (2) यह मानता है कि संघ द्वारा कर लगाने की मांग की गई आय राज्य की आय है, लेकिन सबसे पहले इस सवाल का अतर दिया जाना चाहिए कि क्या अनुच्छेद 289 के खंड (1) के संदर्भ में, अपीलकर्ता/प्राधिकरण की आय

राज्य की आय है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974, विशेष रूप से उसकी धारा 17 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम के तहत गठित अपीलकर्ता/प्राधिकरण की आय उसकी अपनी आय है और अपीलकर्ता/प्राधिकरण की आय अपने स्वयं के धन का प्रबंधन करता है। इसकी अपनी संपत्तियां और देनदारियां हैं। यह अपने नाम पर मुकदमा कर सकता है या मुकदमा दायर कर सकता है। भले ही, यह अनुच्छेद 289 के खंड (2) के दायरे में कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं करता है, फिर भी यह राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत गठित एक प्राधिकरण है, जिसका एक विशिष्ट कानूनी व्यक्तित्व है, एक कॉर्पोरेट निकाय होने के नाते, राज्य से भिन्न है। अधिनियम की धारा 17 आगे स्पष्ट करती है कि इसके विघटन पर ही इसकी संपत्ति, निधि और देनदारियां राज्य सरकार को हस्तांतरित होती हैं। इसलिए आवश्यक रूप सेए इसके विघटन से पहले, इसकी संपत्तियांए निधियां और देनदारियां इसकी अपनी हैं। इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि अपीलकर्ता/प्राधिकरण की आय राज्य सरकार की आय है, भले ही प्राधिकरण का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम के तहत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किया गया हो।

12. भारत के संविधान पर बसु की टिप्पणी के अनुसार (छठा संस्करणए पृष्ठ 50, खंड (एल) अनुच्छेद 285 और 289 एक दूसरे के अनुरूप हैं, जबकि अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट देता है, अनुच्छेद 289 राज्य की संपत्ति को कराधान से छूट देता है। जबकि अनुच्छेद 289 का खंड (1) सरकारी या गैर.सरकारी गतिविधियों से प्राप्त राज्य की किसी भी आय को संघ कराधान से छूट देता है, खंड (2)एक अपवाद प्रदान करता है, अर्थात्, व्यापार या व्यवसाय से राज्य द्वारा प्राप्त आय कर योग्य होगी, बशर्ते कि संसद द्वारा इस संबंध में एक कानून बनाया गया हो। अनुच्छेद 289 का खंड (3) अनुच्छेद 289 के खंड (2) द्वारा निर्धारित अपवाद का एक अपवाद है और यह प्रदान करता है कि विशेष व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त आय को संघ कराधान से मुक्त किया जा सकता है यदि संसद ऐसे व्यापार या व्यवसाय को सरकार से सम्बंध कार्य से आकस्मिक घोषित करती है (जोर दिया गया) वज़ह साफ है। संविधान के तहत, राज्य को कृषि आय के अलावा किसी भी आय पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। संविधान के तहत, "आय" पर कर लगाने की शक्ति केवल संघ में निहित है। इसलिए, जबकि संघ की कोई भी संपत्ति अनुच्छेद 285 (1) के तहत राज्य कराधान से मुक्त है, व्यवसाय से राज्य द्वारा प्राप्त आय, जैसा कि सरकारी उद्देश्यों से अलग है, को संघ कराधान से छूट नहीं मिलेगी जब तक कि संसद ऐसे व्यापार या व्यवसाय को अवैध

राज्य सरकार के सामान्य कार्यों के लिए प्रासंगिक घोषित न कर दे [अनुच्छेद 289{3) देखें]। (जोर दिया गया)

उपरोक्त परीक्षण को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने से यह स्पष्ट है कि करदाता को आयकर अधिनियमए 1961 की धारा 10(20ए) द्वारा प्रदत्त लाभ स्पष्ट रूप से छीन लिया गया है। इसके अलावा, धारा 10(20) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण "स्थानीय अधिकारियों" की गणना करता है जो यहां निर्धारिती को कवर नहीं करते हैं। इसलिए, हमें निर्धारिती की ओर से पेश किए गए आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिली।

13 आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम।आयकर अधिकारी, बीआई बी-वार्ड हैदराबाद, और अन्य, सवाल यह उठा कि क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत स्थापित आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय, संविधान अनुच्छेद के 289 (1) के अर्थ के तहत आंध्र प्रदेश राज्य की आय नहीं थी और इसलिए संघ कराधान से छूट दी गई। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 289 की योजना पर विचार किया और इस प्रकार देखा:-

> "अनुच्छेद 289 की योजना यह प्रतीत होती है कि आम तौर पर किसी राज्य द्वारा सरकारी और गैर.सरकारी या वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त आय संघ द्वारा लगाए

गए आयकर से मुक्त होगी, बशर्ते, प्रश्न में आय को राज्य की आय होना कहा जा सकता है यह सामान्य प्रस्ताव खण्ड (1) से प्रवाहित होता है।"

खंड (2) तब एक अपवाद प्रदान करता है और संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त आय के संबंध में कर लगाने का अधिकार देता है; कहने का तात्पर्य यह है किए किसी राज्य की सरकार या उसकी ओर से किए गए व्यापार या कारोबार से होने वाली आय, जो खंड (1) के तहत कर योग्य नहीं होती, पर कर लगाया जा सकता है, बशर्ते कि इस संबंध में संसद द्वारा एक कानून बनाया गया हो। यदि खंड (1) अपने आप में कायम होता, तो किसी राज्य द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त आय को इसके दायरे में शामिल करना आसान नहीं होता, लेकिन चूंकि खंड (2)संसद को किसी राज्य द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर कर लगाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि इन गतिविधियों को खंड (1) में शामिल माना गया है और केवल यही उन शब्दों का औचित्य हो सकता है जिनमें खंड (2) संविधान द्वारा को अपनाया गया है, यह स्पष्ट है कि खंड (2) इस

आधार पर आगे बढ़ता है कि इसके प्रावधान के अलावा, इसके अंतर्गत आने वाली व्यापारिक गतिविधि ने खंड (1) के तहत संघ कराधान से छ ट का दावा किया होगा। यह खंड (1)और (2) एक साथ पढ़ने का परिणाम है।

खंड (3) तब संसद को कानून द्वारा यह घोषित करने का अधिकार देता है कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय को खंड (2) के दायरे से बाहर ले जाया जाएगा और खंड (1) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यह घोषित करके बहाल किया जाएगा कि उक्त व्यापार या व्यवसाय सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक है। दूसरे शब्दों में, खंड (3) खंड (2) द्वारा निर्धारित अपवाद का अपवाद है। जो भी व्यापार या व्यवसाय सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक घोषित किया जाता हैए वह खंड;2द्ध द्वारा शासित होना बंद हो जाएगा और फिर संघ कराधान से मुक्त हो जाएगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो यह अनुच्छेद 289 के तीन खंडों द्वारा अपनाई गई योजना का परिणाम प्रतीत होता है।''

14. इन तीन खंडों को एक साथ पढ़ते हुए इस न्यायालय ने माना कि संपत्ति और आय जिसके संबंध में खंड (1) के तहत छूट का दावा किया गया है, राज्य की संपत्ति और आय होनी चाहिए, और इस प्रकार उत्तर दिया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है: "क्या राज्य द्वारा अपनी परिवहन गतिविधियों से प्राप्त आय राज्य की आय है"? यह देखा गया कि यदि कोई व्यापार या व्यवसाय किसी राज्य द्वारा विभागीय तौर पर या उस उद्देश्य के

लिए विशेष रूप से नियुक्त एजेंटों के माध्यम से किया जाता है, तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि ऐसे व्यापार या व्यवसाय से होने वाली आय राज्य की आय है। कठिनाइयाँ तब उत्पन्न होती हैं जब कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक अधिसूचना जारी करके किसी राज्य द्वारा स्थापित निगम द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय से निपट रहा होता है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा:-

> "...निगम, हालांकि वैधानिक है, उसका अपना एक व्यक्तित्व है और यह व्यक्तित्व राज्य या अन्य शेयरधारकों से अलग है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई शेयरधारक निगम की संपत्ति का मालिक है या उस व्यवसाय को करता है जिससे निगम संबंधित है। यह सिद्धांत कि एक निगम की अपनी एक अलग कानूनी इकाई होती है, सामान्य कानून से प्राप्त हमारी धारणाओं में इतनी दृढ़ता से निहित है कि इसके साथ विस्तृत रूप से निपटना शायद ही आवश्यक है; और इसलिए, प्रथम दृष्टया, अपीलकर्ता द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय का दावा राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता है जो निगम के शेयरधारकों में से एक है।"

15. इस न्यायालय ने उस अधिनियम की योजना पर विचार किया जिसके तहत राज्य निगम का गठन और आयोजन किया गया था:-

> "..इस चरण में हम जिस मुख्य बिंदु की जांच कर रहे हैं वह यह है; क्या अपीलकर्ता द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय, अनुच्छेद 289(1) के तहत चरण की आय है? हमारी राय में, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। निगम की आय को राज्य की आय बनाने वाला कोई प्रावधान करना तो दूर, सभी प्रासंगिक प्रावधान निगम के अलग व्यक्तित्व को जोरदार ढंग से सामने लाते हैं और इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि व्यापारिक गतिविधि निगम द्वारा संचालित होती है और लाभ और निगम का घाटा अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निगम के चेहरे से पर्दा हटाने का प्रयास करता हो और इस तरह शेयरधारकों को यह दावा करने में सक्षम बनाता हो कि संगठन ने जो रूप ले लिया है, उसके बावजूद, यह शेयरधारक ही हैं जो व्यापार चलाते हैं और जो दावा कर सकते हैं इससे होने वाली आय उनकी अपनी है। धारा 28 जो ब्याज के भुगतान का प्रावधान करती हैए एक ओर

निगम और दूसरी ओर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से द्वंद्व को सामने लाती है। उदाहरण के लिए धारा 38 द्वारा अधिकृत निगम के अधिक्रमण के मामले को लें। धारा 38(2)(सी) जोरदार ढंग से इस तथ्य को सामने लाती है कि संपत्ति वास्तव में निगम में निहित है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि अधिक्रमण की अवधि के दौरान, यह राज्य सरकार में निहित होगी इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय को अनुच्छेद 289(1) के तहत राज्य की आय नहीं कहा जा सकता है, और यदि ऐसा है, तो यह तथ्य है कि अपीलकर्ता द्वारा की गई व्यापारिक गतिविधि अनुच्छेद 289(2) के अंतर्गत आ सकती है, वास्तव में अपीलकर्ता के मामले में सहायता नहीं करती है। भले ही कोई व्यापारिक गतिविधि अनुच्छेद 289 के खंड (2) के अंतर्गत आती है, यह केंद्रीय कराधान से छूट के लिए दावा तभी कायम कर सकती है जब यह दिखाया जाए कि उक्त व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय राज्य की आय है। इस प्रकार अंततः, समस्या की जड़ यह निर्धारित करना है कि क्या विचाराधीन आय राज्य की

आय है और इस महत्वपूर्ण परीक्षण मेंए अपीलकर्ता विफल रहता है।''

16. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों पर काफी भरोसा किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिसके तहत अपीलकर्ता/प्राधिकरण की स्थापना की गई है, उसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर देते हुए कि जैसा कि आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम मामले में है, वैसे ही वर्तमान मामले में भी, अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि अपीलकर्ता/प्राधिकरण के विघटन पर, प्राधिकरण द्वारा वसूली जाने वाली संपत्तियां, धन और बकाया इसकी देनदारियां राज्य सरकार पर आ जाएंगी। इसलिए, निहितार्थ यह है कि ऐसी संपत्तियां, निधियां और बकाया प्राधिकरण के विघटन तक उसके पास निहित रहते हैं और उसके बाद ही यह राज्य सरकार में निहित होते हैं। उन्होंने अधिनियम के कई अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया और कहा कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निगम के चेहरे से पर्दा हटाने का प्रयास करता हो। भले ही प्राधिकरण विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत बनाया गया था, फिर भी यह एक प्राधिकरण था

जिसका अपना एक अलग व्यक्तित्व था, जिसमें शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर थी, जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान और अनुबंध करने की शक्तियां थीं। और अपने नाम पर मुकदमा कर सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरी ओरए श्री वेणुगोपाल ने इस आधार पर फै सले को अलग करने की कोशिश की कि आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम को व्यावसायिक आधार पर चलाया जा रहा है, और एक निगम जो व्यवसायिक आधार पर चलता है, वह उस निगम से अलग और भिन्न है जो व्यवसाय के आधार पर नहीं चलता है। यहां तक कि अगर ऐसा कोई अंतर निकाला भी जाता है, तो ऊपर देखी गई अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसका निगम की आय को राज्य सरकार की आय बनाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. श्री वेणुगोपाल ने तब इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया [1970] 3 एस.एस.सी.323 श्री रामतनु सहकारी हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [1997] 7 एस.एस.सी 339; नई दिल्ली नगरपालिका समिति बनाम, पंजाब राज्य। श्री रामतनु सहकारी आवास सोसायटी में: त्वरित अपील में विचार हेतु जो प्रश्न उठता है वह उठा ही नहीं। सवाल यह था कि क्या महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 को अधिनियमित करने के लिए सक्षम था और क्या विवादित कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 43

सूची । के अंतर्गत आता है, ताकि केवल संसद को ही ऐसा कानून बनाने का अधिकार हो और महाराष्ट्र राज्य को नहीं। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्यों और प्रावधानों के संदर्भ में अधिनियम के वास्तविक चरित्र दायरे और इरादे पर विचार किया। निगम के कार्यों और शक्तियों से संबंधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम वास्तव में उद्योगों की स्थापना, विकास और संगठन, उसके लिए भूमि अधिग्रहण और कार्यान्वयन के लिए निगम को सरकार के अंगों या एजेंसियों में से एक के रूप में स्थापित करके अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना। यह माना गया कि भले ही निगम को भूमि, भवनों और अन्य संपत्तियों के निपटान से धन प्राप्त हुआ और किराए और लाभ भी प्राप्त हुए, ऐसी प्राप्तियां किसी व्यवसाय या व्यापार से नहीं बल्कि उद्योगों की स्थापना, वृद्धि और विकास के एकमात्र उद्देश्य से उत्पन्न हुईं। निगम एक व्यापारिक निगम नहीं था,क्योंकि यह खरीद या बिक्री गतिविधि में शामिल नहीं था। निगम का असली चरित्र औद्योगिक संपदाओं और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विकास करके औद्योगिक शहरों के विकास के एक वास्तुशिल्प एजेंट के रूप में कार्य करना था। इसलिए, यह इस तर्क को नकारता है कि निगम एक व्यापारिक कंपनी है, विवादित विधान सातवीं अनुसूची की सूची ।की प्रविष्टि 43 के अंतर्गत आता है।

यह निर्णय अपीलकर्ता को मदद नहीं करता है क्योंकि भले ही यह माना जाता है कि अपीलकर्ता/प्राधिकरण एक व्यापारिक प्राधिकरण नहीं है, फिर भी यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है कि क्या प्राधिकरण की आय राज्य की आय है ताकि अनुच्छेद 289 का खंड (1) को आकर्षित किया जा सके।

18. इसी प्रकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद बनाम पंजाब राज्य और अन्य में निर्णय (सुप्रा) अपीलकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। यह माना गया कि संबंधित अधिनियम के तहत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा लगाए गए संपत्ति/नगरपालिका कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के खंड (1) के अर्थ के तहत कें द्रीय कराधान का गठन करते हैं। राज्य सरकार से संबंधित भूमि या भवनों पर उपरोक्त अधिनियमों के तहत संपत्ति कर की वसूली अनुच्छेद 289 के खंड (1) में निहित जनादेश के आधार पर अमान्य और अक्षम थी। हालांकि, यदि किसी भूमि या भवन का उपयोग या कब्जा किसी भी व्यापार या व्यवसाय का उद्देश्य से किया जाता है, जिसका अर्थ राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला व्यापार या व्यवसाय है, ऐसी भूमि या भवन उक्त अधिनियमों द्वारा लगाए गए संपत्ति कर के अधीन होंगे। दूसरे शब्दों में, खंड (1) के तहत छूट प्राप्त राज्य संपत्ति का अर्थ ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग सरकार के उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि व्यापार या

व्यवसाय के उद्देश्य के लिए। यह एक ऐसा मामला था जहां राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली भूमि और इमारतों पर संपत्ति कर लगाने के संबंध में सवाल उठा था, जो "राज्य सरकार की संपत्ति" थी। वर्तमान मामले में, हम अपीलकर्ता/प्राधिकरण की आय से चिंतित हैं और वही सिद्धांत लागू होते हैं। छूट का दावा तभी किया जा सकता है जब आय को राज्य सरकार की आय कहा जा सके। इस मामले के तथ्यों में, यह मानना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता/प्राधिकरण की आय राज्य सरकार की आय है।

19. भारत संघ के विद्वान वकील ने भी रिपोर्ट किए गए दो निर्णयों [1999]6 एस.एस.सी 74 भारतीय खाद्य निगम बनाम नगर पालिकाए जलालाबाद और अन्य [1999] 6 एस.एस.सी 78 विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के लिए न्यासी बोर्ड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने लगातार यह विचार किया है कि एक कंपनी की विशेषताओं वाले निगम को केंद्र सरकार से अलग माना जाना चाहिए, और अनुच्छेद 285 के तहत कराधान से छूट के लिए पात्र नहीं है। उच्च न्यायालय ने भी अपने आक्षेपित फैसले में और आदेश में इस न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों से जो संघ की संपत्तियों को राज्य कराधान से छूट देता है निपटने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया। हम इसमें रिपोर्ट किए गए मामलों को उपयोगी रूप से

संदर्भित कर सकते हैं ए,आई.आर.(1999) एस.सी.2573 भारतीय खाद्य निगम बनाम नगर पालिका, जलालाबाद और अन्य, (1995)5 एस सी सी 251 दम दम नगर पालिका के नगर आयुक्त और अन्य बनाम भारतीय पर्यटन विकास निगम और अन्य,;(1994) साप 3 एससीसी 316 केन्द्रीय भंडारण निगम बनाम नगर निगम और एआईआर (1982) एससी 697 और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोरबां एवं अन्य।

20. मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि अपीलकर्ता/प्राधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 289(1) के तहत केंद्रीय कराधान से छूट का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, आयकर अधिकारियों द्वारा जारी किया गया नोटिस वैध और कानूनी था और इसे रिट याचिका में सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तदनुसार, यह अपील खारिज की जाती है लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सूवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती शालिनी चौधरी (आरजेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।